सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने जल संचय अभियान का शुभारंभ किया

उदयपुर में भी प्रताप गौरव केन्द्र परिसर में वर्षा जल संचय के लिए रिचार्ज वैल का निर्माण किया गया है

उदयपुर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मंगलवार को प्रताप गौरव केन्द्र ''राष्ट्रीय तीर्थ'' पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप की विशाल बैठक प्रतिमा पर पुष्पांजलि नमन के साथ केन्द्र के परिसर पर ''कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान'' के तहत जल संचय-जन भागीदारी के अन्तर्गत बोरवैल का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया।

जल संरक्षण हेतु जनभागीदारी सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत आमजन एवं संस्थाओं को जोड़ने के क्रम में प्रताप गौरव केन्द्र में रिचार्ज वैल का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। अतिथियों के केन्द्र पहुंचने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रसाद शर्मा, केन्द्र के निदेशक अनुराग सक्सेना, सचिव महावीर चपलोत, वरिष्ठ इतिहासविद डॉ. देव कोठारी, जल विशेषज्ञ डॉ. अनिल मेहता, जयदीप आमेटा, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, प्रताप गौरव शोध केन्द्र के निदेशक डॉ. विवेक भटनागर, कैलाश हकीम, दिनेश राजपुरोहित, अनुराग कोठारी, समाजसेवी गजपाल सिंह राठौड़, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, समाजसेवी शंभू गमेती, आर्किटेक्ट सुनील लढ्ढा आदि ने स्वागत किया।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि नमन के साथ केन्द्र परिसर पर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल।

प्रधानमंत्रीं नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू किये गये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय-जन भागीदारी के अन्तर्गत कई लोग भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज वैल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उदयपुर में भी प्रताप गौरव केन्द्र परिसर में वर्षा जल संचय के लिए रिचार्ज वैल का निर्णय किया गया। इस संकल्प के तहत गौरव केन्द्र परिसर में रिचार्ज वैल के कार्य का मंगलवार से श्रीगणेश हुआ।

6 सितंबर, 2024 को गुजरात के सूरत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ''जल संचय जन भागीदारी'' अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत सरकारी और गैर-सरकारी संसाधन सहायता के माध्यम से वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, बोरवेल पुनर्भरण, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण कर भूजल पुनर्भरण किया जाना है। साथ ही भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआर जीएस) और अटल भूजल योजना सहित क कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। इन सामूहिक प्रयास के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करते हुए दस लाख संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में 45 हजार जल संचय संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश के सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, जयपुर व बीकानेर जिलों में कुल 337 कार्य प्रस्तावित है।

- **संकल्प के तहत गौरव केन्द्र परिसर में रिचार्ज वैल के कार्य का शुभारंभ हुआ**

सार-समाचार

राज्य उपभोक्ता आयोग के तीन सदस्यों को दी भावभीनी विदाई

जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर में न्यायिक सदस्य शैलेन्द्र भट्ट, रामफूल गुर्जर एवं संजय टाक के पाँच वर्षीय सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यालय में आयोजित इस विशेष अवसर पर आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति देवेंद्र कछावा, न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन, निर्मल सिंह मेडतवाल एवं उप-पंजीयक जया चतुर्वेदी ने तीनों सदस्यों को श्रीफल भेंट कर माल्यार्पण किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगलकामना की। इस अवसर पर न्यायाधिपति देवेंद्र कछावा ने अपने उद्बोधन में तीनों सदस्यों के उत्कृष्ट कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनका न्यायिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता और समर्पण आयोग के लिए प्रेरणास्त्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि सदस्यों का कार्यकाल गरिमामयी और सराहनीय रहा है, जिसने उपभोक्ता हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ओवर लोडिंग को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सडक़ मंत्रालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि नीमकाथाना और कोटपूतली-बहरोड क्षेत्र में ओवर लोड खनन वाहनों का परिवहन क्यों नहीं रोका जा रहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश खनन ठास्त संघर्ष समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।जनहित याचिका में अधिवक्ता सतीश ने अदालत को बताया कि नीमकाथाना, कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में ओवर लोड खनन वाहनों को सरेआम अवैध परिवहन किया जा रहा है। खनन परिवहन करने वाले अधिक खनन सामठी ले जाने के चलते वाहनों को ओवरलोड करते हैं। वहीं अधिकारी भी तभी कार्रवाई करते हैं, जब किसी ओवरलोड वाहन के कारण दुर्घटना हो जाती है। ओवरलोड वाहन कई बार हाईवे पर संतुलन खोकर पलट जाते हैं और इस दौरान साथ चल रहे दूसरे वाहनों को भी चपेट में ले लेते हैं। अधिक भार के चलते रोड पर भी अतिरिक्त भार पडता है और वह जल्दी क्षितठास्त हो जाती है। याचिका में कहा गया कि ओवरलोड वाहन प्रदूषण भी बढा रहे हैं। हर वाहन एक निश्चित मात्रा में वजन ले जाने के लिए हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ऐसे में वाहन ओवरलोड होने से ईंधन भी अधिक खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है ओवरलोड वाहन का चालान करने के साथ ही अतिरिक्त वजन को वाहन से उतारा जाए। इसके बावजूद इन वाहनों का चालान कर इतिश्री कर ली जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

मिनी बस ने महिला को कुचला

जयपुर। टोंक रोड पर पिंजरापोल गौशाला के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने सडक पार कर रही बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इससे महिला की मौत हो गई। हादसे की जांच दुर्घटना थाना पुलिस पूर्व कर रही है।पुलिस के अनुसार मंगलवार को करीब 4.50 बजे एक 55 वर्षीय महिला रघुनाथपुरी प्रथम के पास सडक पार कर रही थी। इसी दौरान मिडी बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रुप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो गई।

जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक

उदयपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। शर्मा कल सोमवार रात्रि को उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है।

पूर्व मंत्री के आवास पर प्रदर्शन मामले में नरेश मीणा को जमानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन और भीड को उकसाने के मामले में आरोपी नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि आरोपी की ओर से निचली अदालत में जमानत-मुचलके पेश किए जाए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर किसी भी व्यक्ति के कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पूर्व में प्रकरण में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों को जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई की जा रही है। इतना लंबा समय बीतने के बाद पुलिस ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कहा कि उपचुनाव के बाद भीड़ को उकसाने के एक अन्य मामले में नरेश मीणा की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। यह मामला भी समान प्रकृति का है। ऐसे में उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सितंबर, 2023 में नरेश मीणा को किसी अन्य मामले में जमानत मिली थी। इस पर उसके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था।

दो वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए है जो कि चेन और मोबाइल स्नेचिंग भी करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन और 7 मोबाइल भी बरामद किए है। आरोपी चोरी के सामानों को सस्ते में बेचकर अपने नशे की आदत को पुरा करते थे। बदमाश चोरी के वाहनों से मोबाइल व चेन स्नेचिंग की वारदातें करते थे।

पुलिस ने चोरी के मामले में संजय उर्फ डेमू गुर्जर और गीतम उर्फ नैना बैरवा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी इंदिरा गांधी नगर में किराए से रह रहे थे। आरोपियों के पास से तीन मोटर साइकिल और एक स्कूटी के साथ 7 मोबाइल मिले है। आरोपी संजय के खिलाफ वाहन चोरी के वाहन चोरी, मोबाइल और चेन स्नेचिंग के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है।

सरकारी इंजीनियर के लॉकर्स से मिला 50 लाख का सोना-चांदी

जयपुर।जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल के दो बैंक लॉकर खोलने के लिए एसीबी की टीम गंगापुर सिटी पहुंची। दोनों लॉकर में मिले सोने के गहनों का कुल वजन 850 ठाम है। वहीं चांदी के गहनों का वजन सवा किलो हैं। इसकी बाजार कीमत 50 लाख रुपए है। इसके साथ ही एसीबी की कार्रवाई पूरी हो गई है।

डिप्टी अभिषेक की सुपरविजन में दोनों बैंक लॉकर खोले गए। इस दौरान मित्तल के परिवार का एक व्यक्ति एसीबी की टीम के साथ मौजूद रहा। इससे पहले सोमवार को एसीबी को मित्तल के जयपुर स्थित बैंक लॉकर से डेढ़ किलो सोने और 5 किलो चांदी के जेवरात मिले थे।

एसीबी के डीजी रवि प्रकाश ने बताया कि दीपक कुमार मित्तल के जयपुर स्थित घर पर एसीबी ने रविवार को छापेमारी की थी। रविवार को कार्रवाई में एक्सईएन के घर से करीब 50 लाख कैश, आधा किलो सोने के गहने और 1.5 किलो चांदी के गहने मिले थे। कार्रवाई के दौरान एक्सईएन और उसके परिजनों के नाम जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 4 प्लॉट, उदयपुर में 9 प्लॉट (1 करोड़ 34 लाख रुपए), ब्यावर व अजमेर में 6.50 लाख रुपए के 3 प्लॉट मिले थे। मित्तल और परिजनों के कुल 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए मिलने के साथ तीन बैंक लॉकर होने का पता चला था। मित्तल ने म्यूचुअल फंड में करीब 50 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। आरोपी के पास 15 लाख रुपए के वाहन हैं।

दरअसल, एसीबी को इंजीनियर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीबी ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर सर्च शुरू किया था। आरोपी दीपक मित्तल के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और फरीदाबाद (हरियाणा) के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जब से नौकरी पर लगा, तब से आय से 4 करोड़ 2 लाख 14 हजार 395 रुपए की संपत्ति अधिक अर्जित की है। हरियाणा के फरीदाबाद के इस घर में रविवार सुबह एसीबी की टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि यह घर आरोपी के भाई का है।

- **सरकारी इंजीनियर के लॉकर्स से मिला 50 लाख का सोना-चांदी**

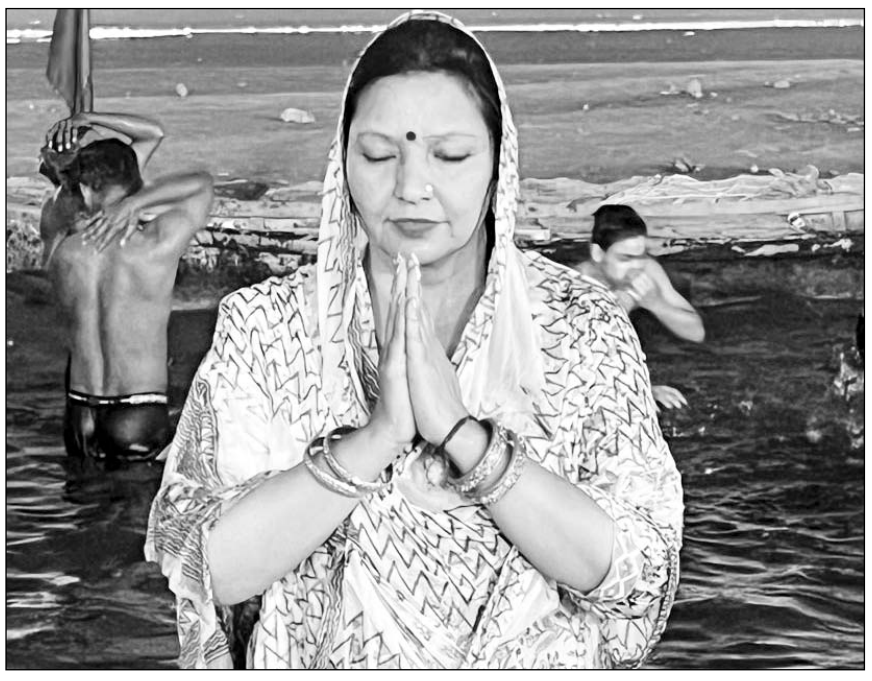

नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान किया। इस दौरान महापौर कुसुम यादव के साथ हेरिटेज निगम के पार्षद और निगम अधिकारियों ने भी स्नान कर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान महापौर कुसुम यादव ने प्रयागराज में संगम तट पर पवित्र गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का विधि विधान से पूजन किया और चुनरी ओढ़ाकर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की।

पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस अधिकारी की हादसे में मौत

जयपुर। पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर फतेह सिंह चौधरी (53) की अलवर में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर अलवर के मुंडावर के माजरा गांव से कार से ड्यूटी जाने के लिए सुबह 5 बजे से पहले निकले थे। राजगढ़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर घायल हो गए। जिला अलवर अस्पताल लेकर आए तो मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मुंडावर के माजरा गांव निवासी पुलिस इंस्पेक्टर फतेह सिंह चौधरी ने मंगलवार तडके करीब 5 बजे से पहले गांव से जयपुर जाने के लिए निकले थे।

खुद की कार से जयपुर जाते समय सुबह करीब साढ़े 5 बजे राजगढ़ के निकट बावड़ी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन उनके कार कार को टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें तुरंत मालाखेड़ा अस्पताल में ले जाया गया।

देश के 152 व राजस्थान के दस नगरीय निकायों में 'नक्शा' की शुरुआत

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का प्रगतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 नगरीय निकायों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस उन्नत भूमि प्रबंधन प्रणाली से शहरी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी तथा लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे। यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी। उन्होंने आमजन को इसमें सहयोग देने की अपील भी की।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि सभी अधिकारी इस प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कर आमजन को जागरूक करें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जनसहयोग आवश्यक है। नक्शा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम कटिबद्ध है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ठामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय ठामीण विकास तथा संचार राज्य मंत्री डॉ चन्द्रशेखर पेम्मसानी द्वारा किया गया। हवाई सर्वेक्षण से सटीक मैपिंग की जायेगी। राज्य सरकारों व नगारिक भागीदारी से भूमि रिकॉड का सत्यापन किया जायेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसान एक्सेस उपलब्ध होने से भू-स्थानिक डेटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी।

सटीक और तेज डेटा संठाहण किया जायेगा। 20 नाडिर कैंमरा की मदद से स्पष्ट और सटीक नक्शों की उपलब्धता हो सकेगी साथ ही आब्लिक एंगल कैमरा की मदद से हर एंगल से सही जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें उन्नत 3डी मैंपिंग के लिए लिडार सेंसर तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा।

सटीक और ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड उपलबध होंगे। शहरी भूमि प्रबंधन में सुधार होगा। उन्नत शहरी भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा साथ ही जमीन से जुडी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेज होगीं।

- **संपत्तियों के सटीक सीमांकन को मिलेगी नई दिशा और दशा : नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री**
- **शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा और गति : नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री**

कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण व स्वरोजगारमुखी बनाया जाये : राजन विशाल

जयपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण एवं स्वरोजगार मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत कृषि महाविद्यालयों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।

शासन सचिव ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संकाय संचालित निजी विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत कृषि महाविद्यालयों के अधिकारियों व पदाधिकारियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने तथा निजी कृषि महाविद्यालयों के संचालन हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं, छात्रों, सभी हितधारकों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु कमेटी के गठन के निर्देश प्रदान करें। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण एवं रोजगार मुखी बनाये जाने पर जोर दिया। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर किये गये बदलाव एवं दिशा-निर्देश के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहीत स्वरोजगार मुखी विषयों को सम्मिलित कर ज्ञान के परिदृश्य में विधार्थियों में उद्यिमता, नैतिकता, तार्किकता, करूणा और संवेदनशीलता विकसित की जा सके जिससे विधार्थी रोजगार के लिये सक्षम बन सके। शासन सचिव ने कृषि विश्वविद्यालय में उत्पन्न पेंशन एवं सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान एवं विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन फण्ड के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं पेंशन की कुलदेयता व विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के लिए रियल स्टेट, अनुसंधान, पेटेन्ट, बीज उत्पादन आदि आय के साधनों के बारे में विस्तृत चर्चा की। विश्वविद्यालय की भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में विश्वविद्यालय के नाम नामान्तरण कराने के निर्देश प्रदान किये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक अर्जित बनर्जी ने कहा कि उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के शैक्षिणक कार्यक्रम को और गतिशील बनाने के लिए समय-समय पर शिक्षण कार्यो में वन विभाग द्वारा सहयोग किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को समर ट्रेनिंग कराये जाने के लिए भी कहा। बैठक में प्रधान वन संरक्षक अनुराग भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक अरूण प्रसाद, आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, उप शासन सचिव कृषि (ठ्ठप-3) अशोक कुमार मीणा, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिनिधि, निजी कृषि विश्वविद्यालयो एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधि अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) एच.एस. मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी) अर्जुन लाल सहित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

कृषि महाविद्यालयों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।

16 साल पुराना बर्खास्तगी आदेश निरस्त

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने किशोरावस्था में किए अपराध की जानकारी नहीं देने पर कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने 6 मई, 2008 को जारी बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभों के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेश कुमार की ओर से 16 साल पहले दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि अदालती आदेश की पालना में समस्त कार्रवाई तीन माह में पूरी की जाए।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किशोर न्याय अधिकरण के तहत किशोर को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है तो अपील का समय समाप्त होने के बाद उसका समस्त रिकॉर्ड हटा दिया जाता है। ऐसे में किसी किशोर को उसके अतीत में किए अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अतीत के अपराध के कारण उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसे एक नई शुरुआत का अवसर दिया जाना चाहिए।

प्राथमिकता से हों लाइन मेंटिनेंस के काम : डिस्कॉम्स चेयरमैन डोगरा

जयपुर सिटी सर्किल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

जयपुर। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने जयपुर सिटी सर्किल के अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि आने वाली गर्मियों में उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में बढोतरी का आकलन करते हुए लाइन मेंटिनेंस के काम अभी से पूर्ण कर लिए जाएं।

डोगरा जयपुर शहर वृत्त उत्तर एवं दक्षिण के अभियंताओं के साथ मंगलवार शाम को विद्युत भवन में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रही थीं।

उन्होंने सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे ट्रिपिंग की समस्या वाले क्षेत्रों में एचटीएम विंग के अभियंताओं के साथ जीएसएस का निरीक्षण करें और वहां मेंटिनेंस के काम को प्राथमिकता से पूरा कराएं। भार के अनुरूप अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। केबल, रोस्टर स्विच, आइसोलेटर, वीसी ब्रेकर जैसे आवश्यक लाइन मैटेरियल की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने मुख्य अभियंता (मैटेरियल मैनेजमेंट) को निर्देश दिए कि इन सर्किलों में मांग के अनुरूप आवश्यक लाइन मैटेरियल की समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (आईटी) को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से नो करेंट की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका विश्लेषण करें ताकि अगली बैठक में क्षेत्रवार शिकायतों के संबंध में समीक्षा की जा सके। गर्मियों में लोड का बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी ट्रिपिंग के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके।